



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228148
CG-DL-E-06072021-228148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2516]
No. 2516]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2717(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ बासठवां संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, -

(क) प्रथम अनुसूची में,-

(i) "1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उप शीर्षक "(i) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित उप शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग";

(ii) "8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप शीर्षकों के पश्चात्, विद्यमान शीर्षक "8क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय" और "8ख. संस्कृति मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखे जाएंगे अर्थात्:-

8क. सहकारिता मंत्रालय

8ख. कारपोरेट कार्य मंत्रालय

8ग. संस्कृति मंत्रालय

(ख) द्वितीय अनुसूची में,-

(i) “कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,

(क) उप शीर्षक ‘क. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग’ के स्थान पर निम्नलिखित उप शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

“क. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग”;

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक “क. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग” के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों 24, 25, 26, 27 और 28 का लोप किया जाएगा;

(ii) “रसायन और उर्वरक मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, उप शीर्षक “ख. उर्वरक विभाग” के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

“2. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार यूरिया के संचालन और वितरण के लिए आबंटन और पूर्ति संपर्क”;

(iii) “उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” शीर्षक के पश्चात और उप शीर्षक “ख. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग” और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

“सहकारिता मंत्रालय”

1. सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और सभी सेक्टरों में सहकारिता क्रियाकलापों का समन्वय।
टिप्पणी: संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के लिए उत्तरदायी हैं।
2. “सहकारिता से समृद्धि” संबंधी सपने को साकार करना।
3. देश में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाना तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुंच बनाना।
4. सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना, जिसमें देश के विकास हेतु इसके सदस्यों में जिम्मेदारी की भावना का संवर्धन है।
5. समुचित नीति, विधिक और संस्थागत कार्यवाही सृजित करना जिससे सहकारिता अपनी क्षमता को हासिल कर सके।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले।
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
8. एक ही राज्य में सीमित न रह जाने के उद्देश्य के साथ सहकारी सोसाइटियों का निगमीकरण, विनियमन तथा समापन, जिसमें ‘बहु-राज्य सहकारिता सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39)’ शामिल है।
परन्तु मल्टी मॉडल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही सहकारी इकाइयों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग ‘केन्द्रीय सरकार’ होगी।
9. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदधारियों तथा अशासकीय सदस्यों की शिक्षा शामिल है)।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/7/2021-मंत्रि.]
आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2717(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixty Second Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
 - (a) in THE FIRST SCHEDULE, -
 - (i) under the heading “1. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Krishi Evam Kisan Kalyan Mantralaya)”, for the sub-heading “(i) Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Krishi, Sahkarita Evam Kisan Kalyan Vibhag)”, the following sub-heading shall be substituted, namely:-

“(i) Department of Agriculture and Farmers Welfare (Krishi Evam Kisan Kalyan Vibhag)”;
 - (ii) after the heading “8. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvajanic Vitaran Mantralaya)” and sub-headings thereunder, for existing headings “8A. Ministry of Corporate Affairs (Corporate Karya Mantralaya)” and “8B. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)”, the following headings shall be substituted, namely; -

“8A. Ministry of Cooperation (Sahkarita Mantralaya);
8B. Ministry of Corporate Affairs (Corporate Karya Mantralaya);
8C. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)”;
 - (b) in THE SECOND SCHEDULE,-
 - (i) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)”,
 - (A) for the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE (KRISHI, SAHKARITA EVAM KISAN KALYAN VIBHAG)”, the following sub-heading shall be substituted, namely: -

“A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN VIBHAG)”;
 - (B) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN VIBHAG)” as so substituted, the existing entries 24, 25, 26, 27 and 28 shall be omitted;
 - (ii) under the heading “MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF FERTILIZERS (URVARAK VIBHAG)”, for existing entry 2, the following entry shall be substituted, namely: -

“2. Allocation and supply linkages for movement and distribution of urea in terms of assessment made by the Department of Agriculture and Farmers Welfare”;
 - (iii) after the heading “MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)”, and sub-heading “B. DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (KHADYA AUR SARVAJANIK VITRAN VIBHAG)” and entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:-

“MINISTRY OF COOPERATION (SAHKARITA MANTRALAYA)

1. General Policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors.

Note: - The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields.

2. Realisation of vision “from cooperation to prosperity”.
3. Strengthening of cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots.
4. Promotion of cooperative-based economic development model, including the spirit of responsibility among its members to develop the country.
5. Creation of appropriate policy, legal and institutional framework to help cooperatives realise their potential.
6. Matters relating to National Co-operative Organisation.
7. National Co-operative Development Corporation.
8. Incorporation, regulation and winding up of Co-operative societies with objects not confined to one State including administration of ‘the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002)’:

Provided that the administrative Ministry or Department shall be ‘the Central Government’ for the purpose of exercising powers under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), for Co-operative units functioning under its control.

9. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).”.

Ram Nath Kovind
President

[F. No. 1/21/7/2021-Cab.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.